म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान

(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, मानव विकास संसाधन मंत्रालय,
भारत सरकार का एक स्वायत्त शोध संस्थान)
6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन – 456 010 (म. प्र.)

राष्ट्रीय सेमिनार

ग्रामीण भारत का बदलता परिदृश्य एवं सरकारी कार्यक्रमः चुनौतियाँ, अवसर एवं सम्भावनाएँ

(Changing Scenario of Rural India and Governmental Programmes: Challenges, Opportunities and Possibilities)

(मार्च 15–16, 2017)

प्रायोजक – उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

भारत ग्रामीण समुदायों की भूमि रहा है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण चरित्र की प्रमुखता यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत से प्रतिबिम्बित होती रही है। 83.3 करोड़ से अधिक लोग गांवों में रहते है एवं ऐसे में भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की कोई भी रणनीति ग्रामीण लोगों एवं क्षेत्रों की अवहेलना कर सफल नहीं हो सकती। अतः ग्रामीण विकास भारत की एक निरपेक्ष त्वरित आवश्यकता रही है एवं यह आने वाले समय में भी बनी रहेगी।

स्वतंत्रता के सात दशकों के पश्चात् भी जब हम ग्रामीण क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं तो स्थितियाँ बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं कही जा सकती है। नियोजित विकास के छः दशकों से अधिक समय के पश्चात भी ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बाल मृत्युदर एवं लैंगिक असमानता जैसी बुराइयों से ग्रस्त है। ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, बिजली, सिंचाई, पेयजल, सड़क जैसे कमोबेश सभी आधारभूत क्षेत्रों में स्थितियाँ अपेक्षित लक्ष्यों से बहुत नीचे हैं। यह सन्दर्भ ज्यादा तर्कसंगत एवं समीचीन प्रतीत होता है जब प्रारम्भ से लगाकर वर्तमान तक ग्रामीण विकास हमारी सम्पूर्ण नियोजन प्रक्रिया में सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है तब भी हम लक्ष्यों से इतने दूर क्यों रह गये। इसके पीछे कई कारण हैं लेकिन इनमें कुछ बाते ऐसी है जो हमारे सम्मुख मौलिक सवाल खड़े करती है। सामान्य तौर पर उनमें कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति, दोहरापन, सामंजस्य का अभाव, सामाजिक अन्तर्सम्बद्धता की अनुपस्थिति, प्रशासनिक लेट–लतीफी एवं अनावश्यक खर्च, जनसामान्य की भागीदारी का अभाव और कई अन्य ऐसे कारणों को इनमें गिनाया जा सकता है। इसके कारण अच्छी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बावजूद कमजोर एवं लचर आपूर्ति व्यवस्था ने अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति में एक बड़ी रूकावट या अवरोध पैदा किया।

नब्बे के दशक में दो प्रमुख प्रतिमान ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। पहला आर्थिक सुधार एवं दूसरा विकेन्द्रीकृत अभिशासन। वैश्विक एवं स्थानीय स्तर के इन सुधारों ने ग्रामीण विकास की नीतियों, कार्यक्रमों एवं रणनीतियों में बहुत परिवर्तन किए जिसके प्रत्यक्ष परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें जा सकते हैं। सतत् आजीविका से जुड़े मुद्दे कुपोषण, बीमारी, अभाव, निरक्षरता, मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं की कमी इत्यादि को इन नीतियों में सम्बोधित करने का प्रयास किया गया है। इस नीति में द्विआयामी रणनीति पर अमल किया गया जिसमें निर्धनता के विरूद्ध सीधी कार्यवाही एवं सामाजिक क्षेत्रों में प्रभावी निवेश सम्मिलित है। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासन एवं जनसहभागिता के द्वारा विकास हेतु ग्रामों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना। साथ ही इस प्रणाली में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। सरकार द्वारा विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके उनके साथ रोजगार को जोड़ा गया। ये ग्रामीण गरीबों को उत्पादक सम्पत्ति के सृजन के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजक परिसम्पत्तियों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बैंको एवं शासकीय अनुदान के माध्यम से करोड़ो की संख्यां में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक विकास जैसे सड़क, साफ–सफाई, पेयजल, आवश्यक भवनों, बिजली आदि उपलब्ध कराने के प्रयास भी अग्रणी रहे हैं।

इसी क्रम में वर्तमान सरकार ने इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए विगत दो वर्षों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई नवीन पहल करते हुए कई नयें कार्यक्रमों एवं नवाचारों को प्रारम्भ किया है। इसी कड़ी में वित्तीय समावेशन के माध्यम से सदियों से वंचित कमजोर एवं ग्रामीण समाज को बैंकिंग तन्त्र से जोड़ा गया। साथ ही अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना आदि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रयास किए गये। किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की दिशा में भी कई प्रयास किये गये। कृषि से जुड़ी सरकारी नीतियों में भी काफी परिवर्तन किया गया। कृषि लागत घटाने की दिशा में भी सरकार ने कई प्रयास किये हैं।

भारत की 65 प्रतिशत युवा आबादी के कौशल विकास लिए जहाँ एक ओर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई है तों वही युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देने हेतु मुद्रा बैंक, स्टार्ट अप इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया और मेक इन इण्डिया जैसी योजनाए भी लाई गई आदिवासियों के लिए वनबन्धु कल्याण, श्रमिको के लिए विशिष्ट पहचान पत्र, देश की कला एवं शिल्प को सहेजने के लिए उस्ताद योजना कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण विकास की दिशा में प्रमख योजनाएँ हैं – प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इण्डिया,

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैण्ड अप इण्डिया योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसान विकास पत्र, कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इत्यादि, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)। इसके साथ ही पहले से जारी योजनाओं को भी नये स्वरूप देकर उनका विस्तार किया गया है।

कुल मिलाकर ग्रामीण विकास की दिशा में ये कदम ग्रामीणों की भोजन, आवास, आजीविका, रोजगार सहित सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं को सम्बोधित करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में विषय की महत्ता एवं प्रासंगिकता के दृष्टिगत म. प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन, "ग्रामीण भारत का बदलता परिदृश्य एवं सरकारी कार्यक्रमः चुनौतियाँ, अवसर एवं सम्भावनाएँ" विषय पर दो दिवसीय सेमिनार (15 एवं 16 मार्च, 2017) का आयोजन कर रहा है।

सेमीनार का मुख्य उद्देश्य भारत में विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण परिदृश्य में बदलाव और विकास की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं रणनीतियों में आये परिवर्तनों एवं प्रभावों का विवेचन करना है।

सेमिनार के प्रस्तावित उपशीर्षक इस प्रकार है –

- भारत में ग्रामीण विकास की बदलती प्रवृत्ति एवं दृष्टिकोण
  (Changing Patterns and Perspectives of Rural Development)
- गरीबी उन्मूलन की नीतियों, रणनीति एवं कार्यक्रमों में बदलावं
  (Changing Policies, Strategies and Programmes of Poverty Alleviation)
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का बदलता परिदृश्य
  (Changing Scenario of Employment Generation in Rural Areas)
- न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कल्याण एंवं विकासात्मक कार्यक्रम.
  (Welfare and Development Programmes for Minimum Basic Needs)
- आधारभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचनात्मक विकास
  (Infrastructural Development for Basic Amenities)
- विकेन्द्रीकृत शासन एवं उत्तरदायी प्रशासन.
  (Decentralised Governance and Responsive Administration)
- विकास एवं पर्यावरण.
  (Development and Environment)
- विकास एवं वंचना
  (Development and Deprivation)
- विकास एवं कृषक
  (Development and Farmers)

इस सेमिनार हेतु उक्तांकित विषयवस्तु एवं मुद्दों पर शोध पत्र आमंत्रित हैं। चयनित शोध पत्रों के लेखकों को सेमिनार भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। सेमिनार में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा तथा आवास एवं अन्य व्यवस्थाएँ भी संस्थान द्वारा की जायेगी।

शोध संक्षेपिका (Abstract) भेजने की अंतिम तिथि : 15 फरवरी, 2017
सम्पूर्ण शोध पत्र (4000–6000 शब्द) भेजने की अंतिम तिथि : 24 फरवरी, 2017

डॉ. आशीष भट्ट
सेमिनार समन्वयक
(drabhatt@yahoo.com)

प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया
निदेशक
mailboxmpissr@gmail.com